Summary of Hindu

02-04-2023

हिन्दी माध्यम

ACHIEVERSIASPATNA@GMAIL.COM
+918434931877, +917250667974

राष्ट्रीय

कोई मूर्ति नहीं, कोई हथियार नहीं:

पट्टनम रहस्य पट्टनम केरल के एर्नाकुम जिले का एक गाँव है, इस गाँव में हाल ही में हुई खुदाई में 45 लाख से अधिक टुकड़े (सिरेमिक के टुकड़े) निकले हैं; इसमें भूमध्यसागरीय क्षेत्रों, नील नदी, लाल सागर, पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर से संबंधित 1.4 लाख श्रेड शामिल हैं; हाल के निष्कर्षों में एक स्फिंक एक्स (प्राचीन क्यूरीक सिटी थेर्ब्स के मूल निवासी) की मुहर शामिल है।
उत्खनन निष्कर्ष 5 वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5 वीं शताब्दी ईस्वी तक संपन्न शहरी केंद्र के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, केवल 1% उत्खनन पट्टनम में देवताओं और देवताओं की मूर्तियों, या जाति, पंथ के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान करने वाले संकेत नहीं मिले हैं।

मार्च 1.6 लाख या का दूसरा उच्चतम जीएसटी संग्रह देखता है।

मार्च में भारत का GST 13% बढ़ा। 2022-23 में सकल जीएसटी संग्रह 2021-22 की तुलना में 22% अधिक है।
अगस्त मासिक संग्रह 2022-23 → 1.51 लाख करोड़।
अप्रैल 2022 में एक महीने में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ है। मार्च 2023 में 1.6 लाख करोड़ अब तक का दूसरा सबसे अधिक संग्रह है।

मैक्रॉन ने मोदी को बैस्टिल डे परेड में आमंत्रित किया

मैक्रॉन ने मोदी को बैस्टिल डे परेड में आमंत्रित किया सूत्रों ने पुष्टि की है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने पीएम मोदी को 14 जुलाई को बैस्टिल डे के लिए आमंत्रित किया है। इमैनुअल मैक्रॉन को मार्च में दिल्ली का दौरा करना था लेकिन घरेलू कारणों से उन्हें इस यात्रा को रद्द करना पड़ा।
पिछली बार मनमोहन सिंह को 2009 में बैस्टिल डे के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत ने यात्रा की पुष्टि नहीं की है, क्योंकि यह अभी भी विचाराधीन है।
.

राष्ट्रीय

मोदी ने सशस्त्र बलों से खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया

मोदी ने सशस्त्र बलों से खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया सशस्त्र बलों की ऑपरेशन तत्परता की समीक्षा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तीनों सेनाओं से नए और उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और कहा कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. सशस्त्र बलों को आवश्यक हथियारों और तकनीकों से लैस करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पीएम भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे. 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय "तैयार, पुनरुत्थान, प्रासंगिक" था

इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने जानकारी दी कि देश का रक्षा निर्यात 15,920 या 22-23 में पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3,000 करोड़ अधिक है। प्रमुख निर्यात ड्रोनियर -228, 155 मिमी उन्नत टोड आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश सतह से हवा में मिशन, रडार, सिमुलेटर पिनाका रॉकेट सिस्टम, थर्मल इमेजिंग सिस्टम बॉडी आर्मर आदि हैं।

इसके अलावा एलसीए-(तेजस), हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टरों, विमान वाहक रखरखाव मरम्मत गतिविधियों की वैश्विक मांग बढ़ रही है।

व्यापार को रुपये में व्यवस्थित करने के लिए भारत, मलेशिया डॉलर से आगे बढ़े।

विदेश मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि भारत और मलेशिया भारतीय रुपये में व्यापार को निपटाने पर सहमत हो गए हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस विकल्प को संचालित करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। मलेशिया में इसके "संबंधित बैंक" के माध्यम से एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोला जाएगा। "संबंधित बैंक" - मलेशिया का इंडिया इंटरनेशनल बैंक।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आम तौर पर अमेरिकी डॉलर में होता है। हालाँकि जैसे ही रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और रूस को आर्थिक वर्गों का सामना करना पड़ा।

भारत ने भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। 14 मार्च, 2023 को सरकार ने राज्यसभा में घोषणा की कि 18 देशों के बैंकों को आरबीआई द्वारा रुपये में भुगतान निपटाने के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी गई थी। मलेशिया 18 देशों में से एक था।

राष्ट्रीय

- यह भारत और मलेशिया के व्यापारियों को भारतीय रुपये में व्यापार का चालान करने की अनुमति देगा और इस प्रकार व्यापार की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण होगा
- व्यापारी मुद्रा रूपांतरण स्प्रेड पर बचत करने में सक्षम होंगे।

सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद एशियाई देशों में मलेशिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
2021-22 मलेशिया के साथ भारत का व्यापार (19.4 बिलियन) सिंगापुर (30.1 बिलियन), इंडोनेशिया (26.1 बिलियन)
कश्मीर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (केसीसीआई) ने पश्मीना शॉल के खराब परीक्षण को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने पुशिंग शॉल की जब्ती का मुद्दा उठाया है।

पश्मीना शाल क्या है?

पश्मीना शाल कश्मीर घाटी में हजारों कारीगरों द्वारा बनाई गई है। इसे पशमिंग बकरी के बालों से बनाया जाता है। यह विश्व भर में प्रसिद्ध है।

इसे क्या जब्त किया जा रहा है?

सहतूथ फाइबर भारत और यूरोपीय देशों में प्रतिबंधित है, क्योंकि सहूथ लुप्तप्राय है कई कर्मचारी पश्मीना फाइबर को सहतूथ फाइबर के साथ मिलाते हैं। इन खेपों को जब्त कर लिया जाता है क्योंकि यह हवाई अड्डे पर गाल में विफल रहता है। बाद में देहरादून और कोलकाता में परीक्षण के लिए भेजा जाता है। डिलीवरी में देरी होती है और परेशानी का कारण बनती है।
पश्मीना शॉल के निर्यात के आंकड़े क्या हैं?
2018-19 में निर्यात - 305 करोड़ था। धारा 370 के खात्मे के बाद
2019-20 में निर्यात → 272 करोड़।
2020-21 निर्यात → 172 करोड़।
2021-22 निर्यात → 166 करोड़।

सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सरकार ने बताया है कि वह गुरुग्राम में एक परीक्षण केंद्र स्थापित करेगी जो वहां काफी तेजी से साफ हो जाएगा। केसीसीआई ने बताया है कि बाधाएं दूर होने पर निर्यात 1000 करोड़ को पार कर सकता है।

राष्ट्रीय

भारत - रोमानिया बेहतर सहयोग में मदद करने के लिए रक्षा पर समझौता।

रक्षा नीति, योजना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की राज्य सचिव प्रमुख सिमोना कोजोकारू ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारत का दौरा किया था।
दोनों देशों ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारत और रोमानिया पर हस्ताक्षर किए।
समझौता रक्षा में सहयोग को बढ़ावा देगा, रक्षा चिकित्सा वैज्ञानिक अनुसंधान, साइबर रक्षा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और विकास को खोलेगा।
रोमानिया यूरोपीय संघ का सदस्य है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर यूरोपीय संघ की नीति इसके साथ लागू होती है।

समुद्र के नीचे केबल टेलीकॉम कंपनियों में रुचि रखता है

समुद्र के नीचे केबल टेलीकॉम कंपनियों में रुचि रखता है, लेकिन खराब इंटरनेट के साथ अंडमान के संघर्ष को हल करने के लिए तैयार है।
चेन्नई और अंडमान और निकोबार के बीच अंडरसी केबल बी/डब्ल्यू हालांकि 2020 में पूरा हो गया है, लेकिन कनेक्टिविटी को बदलने में सक्षम नहीं है क्योंकि यह पोर्ट ब्लेयर के मुख्य शहर से दूर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है।
प्रमुख इंटरनेट प्रदाता बीएसएनएल के पास अभी भी 44 सेवाएं आदि प्रदान करने वाले कुछ ही केबल हैं।

- **बिहार के दो जिलों में हुई हिंसा में 45 गिरफ्तार।**

जातिगत जनगणना कराने में भाजपा की विफलता के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के साथ आक्रामक होगी कांग्रेस

कांग्रेस को "एंटी ओबीसी" करार देने वाले बीजेपी अभियान के विरोध में विपक्षी पार्टी सत्ताधारी पार्टी पर हमला करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि विपक्षी दल जाति आधारित जनगणना नहीं कराने के लिए भाजपा पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, कांग्रेस इस पर राजद, सपा और जद (यू) के साथ है।

राष्ट्रीय

मोदी कहते हैं, कुछ लोगों ने छवि खराब करने का ठेका दिया है।

“हमारे देश में कुछ लोग हैं जो ऐसा करने के लिए दृढ़ हैं और 2014 से यह प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने मोदी की छवि को धूमिल करने का संकल्प लिया है, इसके लिए इन लोगों ने अलग-अलग लोगों को सुपारी (ठेका) दी है। देश के अंदर कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं और कुछ बाहर से भी काम कर रहे हैं।

मोदी सरकार वनों और वन्यजीवों के संरक्षण पर कानूनों को कमजोर कर रही है।

कांग्रेस ने संशोधित वन संरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा पर हमला किया है, जिसमें वन से लाभ लेने के लिए आदिवासी को अधिक स्वतंत्रता दी गई है।

दुनिया

ट्रम्प "हैरान" लेकिन उनके खिलाफ 'आरोपों' से लड़ने के लिए तैयार हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प की कानूनी टीम तैयार है, और कसम खाई है कि राष्ट्रपति कभी भी जमानत की दाल नहीं उड़ाएंगे और सभी आरोपों से "लड़ने" के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने "चुनाव" चिपकाया। दखल, कंगारू कोर्ट" अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मंगलवार को ट्रंप कोर्ट में पेश होंगे.

पाकिस्तान के हिस्से भोजन के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति की मुहर तक सबसे अधिक हैं;

सहायता से कम से कम 16 लोगों की मौत। पाकिस्तान में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मार्च में एक साल पहले की तुलना में मार्च में रिकॉर्ड 35.37% पर पहुंच गई, पाकिस्तान स्टैटिक्स ब्यूरो ने शनिवार को कहा। मार्च में वार्षिक खाद्य मुद्रास्फीति क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 47.1% और 50.2% थी। हाल ही में कराची में सरकार द्वारा बांटे गए मुफ्त भोजन के लिए हुई भगदड़ में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई।

पाकिस्तान अभी भी आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहा है।

अमेरिकी यात्रा के बाद ताइवान के राष्ट्रपति मध्य अमेरिका पहुंचे।

ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन हमारी यात्रा के बाद घटते सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को ग्वाटेमाला पहुंचीं।

त्साई का गाटेनसला में राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। ग्वाटेमाला के बाद वह बेलीज का दौरा करेंगी।

पूछे जाने वाले प्रश्न -1

चैट जीपीटी के उत्तराधिकारी का अधिस्थगन कॉल

29 मार्च को, एलोन मस्क और एआई विशेषज्ञों के एक समूह ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सिस्टम विकसित करने पर रोक लगाने के लिए एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो ओपन एआई के हाल ही में लॉन्च किए गए चैट जीपीटी से अधिक शक्तिशाली हैं। 1300 हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में सभी एआई प्रयोगशालाओं को कम से कम 6 महीने के लिए तुरंत विराम देने के लिए कहा गया है। GPT-4 से अधिक शक्तिशाली प्रणाली का प्रशिक्षण (चैट GPT)

पत्र क्या कहता है?

एफएलआई (फ्यूचर लाइफ इंस्टीट्यूट) ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि "एआई प्रयोगशालाएं अधिक शक्तिशाली डिजिटल दिमाग विकसित करने और तैनात करने के लिए एक आउट-ऑफ-कंट्रोल दौड़ में बंद हैं, जिसे कोई भी-उनके निर्माता भी नहीं- समझ सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं या विश्वसनीय रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। " Asilomar AI सिद्धांत AI गवर्निंग सिद्धांतों के शुरुआती सेटों में से एक हैं। पत्र में Asilomar AI सिद्धांतों का हवाला दिया गया है कि कैसे AI में प्रगति लोगों की पंक्तियों को गहराई से प्रभावित कर सकती है।

संदर्भ क्या है?

चैट जीपीटी का उपयोग नाटकीय रूप से बढ़ा है। कई फर्मों ने इसे अपनाया है। चैट जीपीटी कोड को ठीक कर सकता है, कई सवालों के जवाब दे सकता है। स्नैप चैट, स्पॉटिफाई जैसी कंपनियों ने खुद को चैट जीपीटी के साथ एकीकृत कर लिया है। Google ने अपनी स्वयं की भाषा आधारित AI Basd को लॉन्च करने की घोषणा की है। सिस्टम Baidu ने एर्नी लॉन्च किया है। MIT मीडिया लैब ने ELSA, AI बॉट विकसित किया है। चैट GPT की तुलना में भाषा आधारित AI के समान और उससे भी अधिक उन्नत विकसित करने में बहुत बड़ी दौड़ रही है।

FLI का पत्र GPT-4 पर क्यों केंद्रित है?

चैट जीपीटी 175 बिलियन पैरामीटर्स पर आधारित है। GPT-4 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर आधारित है। यह GPT-4 को GPT से बेहतर और चैट करने के लिए भाषा की जटिल बारीकियों को सीखने और समझने की अनुमति देता है।

पूछे जाने वाले प्रश्न -1

- साथ ही GPT-4 पाठ और छवि आधारित प्रश्नों को सौंप सकता है। यह इसे जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) के करीब लाता है। हालाँकि इतना शक्तिशाली; GPT-4 के रूप में AI" में सैम ऑल्टमैन के सह-संस्थापक OPEN AI द्वारा बताए गए दुस्साहस, भारी दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा है।
- सैम अल्टमैन ने लिखा, "एक क्रमिक संक्रमण लोगों को नीति निर्माताओं और संस्थानों को यह समझने का समय देता है कि क्या हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से वहां के सिस्टम के लाभों और डाउनसाइड्स का अनुभव करें, हमारी अर्थव्यवस्था को अनुकूलित करें और विनियमन को लागू करें।"

एआई विशेषज्ञों का क्या विचार है?

कई विशेषज्ञ इसे मानवता को एक प्रलय के दिन की ओर तेजी से बढ़ने के रूप में देखते हैं जहां मशीन मनुष्यों पर विजय प्राप्त करेगी। जबकि अन्य इन अग्रिमों को औसत दर्जे की बुद्धिमत्ता के रूप में देखते हैं जो संभावित रूप से अविश्वसनीय हैं।

क्या इसका वांछित प्रभाव होगा?

यह कहना कठिन है कि इस पत्र का Microsoft पर पहले से ही GPT-4 का प्रशिक्षण लेने और GPT-5 विकसित करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के एआई मॉडल का विकास प्रतिबंधात्मक रूप से चल रहा है क्योंकि सरकार के पास वर्तमान में नीतिगत मूर्खों की कमी है एआई विकास को रोकने के लिए। क्या जलवायु परिवर्तन पर देशों पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

यूएन क्यों है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से एक 'सलाहकार राय' देने के लिए कहा गया है कि क्या देशों के पास लोगों को चरम जलवायु से बचाने के लिए कानूनी दायित्व हैं"? कौन सा देश इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लाया? आगे क्या होता है?

पूछे जाने वाले प्रश्न -2

कहानी अब तक:

29 मार्च को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आईसीजे, हेग से कहा गया कि वे यूएनएफसीसी सी के तहत किए गए वादों के आधार पर जलवायु परिवर्तन में कटौती के प्रति देशों के किस तरह के दायित्व पर अपनी राय दें। संकल्प। वानुअतु द्वारा आगे बढ़ाया गया: दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक। पाम चक्रवात से देश तबाह हो गया था जिसने 95% फसलों को नष्ट कर दिया था और 2/3 आबादी को प्रभावित किया था।

संकल्प क्या चाहता है?

मसौदा प्रस्ताव में आईसीजे से दो सवाल पूछे गए

(1) अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों का वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु की सुरक्षा सुनिश्चित करने का क्या दायित्व है?
(2) राज्यों के लिए इन दायित्वों के तहत कानूनी परिणाम क्या हैं, जहां उन्होंने अपनी चूक के कृत्यों से जलवायु परिवर्तन को विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है।
यह पेरिस समझौते (2015), समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक को संदर्भित करता है। आईसीजे को अपनी राय देने में 18 महीने का समय लगना है।

भारत की स्थिति क्या है'?

भारत इस कदम के बारे में विशेष रूप से सतर्क रहा है। भारत इसका सह-प्रायोजक नहीं था। भारत आमतौर पर जलवायु न्याय की आवश्यकता और ग्लोबल वार्मिंग के लिए विकासशील देशों को जिम्मेदार ठहराने का समर्थन करता रहा है। भारत ने एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) की पुष्टि की है और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा आधी बिजली का उत्पादन करने की राह पर है। भारत भी देख रहा है। अमेरिका और चीन जैसी वैश्विक शक्तियां इसका जवाब कैसे दे रही हैं। मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं जिन्होंने प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया है।
वर्तमान में राज्य स्वयं जलवायु परिवर्तन को कम करने की अपनी क्षमता का निर्धारण करते हैं

पूछे जाने वाले प्रश्न -2

संकल्प के प्रायोजक क्या चाहते हैं?

आईसीजे द्वारा एक कानूनी राय, 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की सर्वोच्च वैश्विक अदालत से देशों को जलवायु परिवर्तन की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
विकसित दुनिया द्वारा जलवायु सुधार जैसे मुद्दों पर राय, एनडीसी हासिल नहीं करने वाले देशों के लिए कानूनी दोषारोपण, और सबसे कमजोर छोटे देशों के लिए जलवायु समर्थन पर बारीकी से नजर रखी जाएगी

संकल्प के लिए क्या विचार आया?

इसकी शुरुआत वानुअतु में 27 कानून के छात्रों द्वारा इसके लिए अभियान चलाने से हुई। वानुअतु सरकार। 18 देशों के समर्थन से इसमें समर्थन करता रहा है
यूएनजीए काफी समय से। इसने एक मसौदा तैयार किया और 132 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। वानुअतु के पीएम इस्माइल कलास्कौ ने इसे "महाकाव्य अनुपात के जलवायु न्याय के लिए एक जीत एक जीत" कहा।

आईसीजे की सलाहकार राय बाध्यकारी है?

हालांकि इसकी सलाहकार राय बाध्यकारी नहीं है। लेकिन इसका अवलोकन जलवायु वित्त और जलवायु न्याय को कारगर बनाने में मदद करेगा। ICJ के पास "कानूनी भार और नैतिक अधिकार" है जो इस दिशा में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा
ICJ के मतों ने अतीत में कई मामलों में बहुत सम्मान और बढ़ावा दिया है जैसे कि फिलिस्तीन मुद्दे (दीवार का निर्माण) और परमाणु खतरों पर।

पूछे जाने वाले प्रश्न -3

प्रस्तावित विधेयक न्यायपालिका पर सरकार को सीधे हाथ देगा। कुछ प्रमुख बिंदु हैं -

- ·नेसेट (इज़राइली संसद) द्वारा साधारण बहुमत से ही अदालत के फैसले को पलटा जा सकता है
- ·विधायी निर्णयों की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध रहेगा।
- ·सर्वोच्च न्यायालय अब ज्ञात कानून, सरकार के निर्णयों या नियुक्तियों की तर्कसंगतता का न्याय नहीं कर पाएगा।

जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल अधिक होगा। वर्तमान में 9 में से केवल 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए समिति में। लेकिन इसके बाद जज नियुक्त करने के लिए 5 सरकारी अपॉइंटमेंट होंगे। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार को बहुमत (5) देगा।

सरकार इन बिलों को क्यों आगे बढ़ा रही है?

इज़राइल का वर्तमान गाउट अपने इतिहास में सबसे सही है। लेकिन न्यायपालिका उदारवादी और वामपंथियों के हाथ में है। भयभीत धार्मिक दलों ने तर्क दिया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन खो गया है। भ्रष्टाचार के बदलावों पर शासन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नेतन्याहू को भी फटकार सकता है। नेतन्याहू को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहराने से रोकने के लिए सरकार को न्यायपालिका के पंखों को काटने का समय आ गया है:

श्री नेतन्याहू पीछे क्यों हटे?

विधेयक को सदन के पटल पर रखने के सरकार के कदम का व्यापक विरोध शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों के साथ यह कहते हुए कि सरकार। न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा, एक बार पारित होने के बाद, यह सरकार को अदालतों पर अनियंत्रित शक्तियाँ प्रदान करेगा, जिससे नागरिक नागरिक बनेंगे। नागरिकों के बीच। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब रक्षा मंत्री योह गैलेंट को सरकार की आलोचना करने पर हटा दिया गया।

पूछे जाने वाले प्रश्न -3

- इसके बाद एक स्वत:स्फूर्त विरोध शुरू हो गया जिसमें लगभग 8,00,00 श्रमिकों ने काम बंद कर दिया, उड़ानें बंद कर दी गईं क्योंकि पायलटों ने इसे उड़ाने से इनकार कर दिया, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया और यहां तक कि राजनयिकों ने भी काम से परहेज किया। इस तरह के अभूतपूर्व जनाक्रोश का सामना करते हुए, नेतन्याहू ने अपनी योजना में देरी करने का फैसला किया।

आगे क्या होता है?

एक महीने के लिए न्यायिक सुधारों के साथ रुकने के बाद भी, नेतन्याहू के अधिकांश दक्षिणपंथी समर्थक अभी भी बिल को पारित करने के लिए दृढ़ हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े सार्वजनिक हंगामे के खिलाफ नेतन्याहू इस विधेयक को कैसे पेश कर पाते हैं।